ALL INDIA FAIR PRICE SHOP DEALERS' FEDERATION

Regd. No. District East/Society/273-2011 of Govt. of NCT. of Delhi

Regd. Office : S-562, School Block, 'AKHAND HINDUSTHAN BHAWAN' Shakarpur, Delhi - 110 092, Mobile : 98110 12241/9871421221

Head Office : AC-164, Prafulla Kanan (East), Kestopur, Kolkata - 700 101, West Bengal

Phone : (033) 2591 3871,Mobile : 98301 35530 / 9748777000 / 9830235550,E-mail : gs@aifpsdf.org,Website : www.aifpsdf.org,WhatsApp : 9831241939/9830135530,Facebook : facebook.com@aifpsdf

Ref. No. : AIFPSDF/1505/22

Dated : 13.11.2022

राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक

दिनांक 05/11/2022 को "मुक्तधारा" सभागार, गोल मार्केट, नई दिल्ली में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत दिनांक 05.11.2022 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक का कार्यवृत्त (सारांश)

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ झा की अध्यक्षता में दिल्ली के "मुक्तधारा" सभागार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 17 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पांच राज्यों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने विभिन्न कारणों से उपस्थित नहीं हो पाने के कारण बताते हुए राष्ट्रीय समिति के निर्णयों और कार्यक्रमों का समर्थन किया। आज की बैठक में उपस्थित राज्यों के प्रतिनिधियों ने संबोधित किया और राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के साथ-साथ राज्यों की ज्वलंत समस्याओं को रखते हुए राष्ट्रीय समिति से तत्काल कदम उठाने की मांग की:

1. असम - श्री धरणीधर बोरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बोरा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ उनके राज्य में भी 2G नेटवर्क e-PoS मशीन की उपलब्धता के कारण खाद्यान्न वितरण की बड़ी समस्या है। e-PoS में 5 किलो खाद्यान्न आवंटन होने के बावजूद कम खाद्यान्न दिया जाता है। राज्य सरकार असम के चाय बागानों के प्रबंधन को लाइसेंस देने पर विचार कर रही है, जिससे 3,237 एफपीएस डीलरों का रोजगार छिन जाएगा। PMGKAY के कमीशन का भुगतान रोक दिया गया है। गोदामों से सही तौल में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन एफपीएस डीलरों द्वारा हितग्राहियों को कम खाद्यान्न देने का आरोप है, जो दुखद है, राष्ट्रीय समिति को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने असम इकाई से हमेशा राष्ट्रीय समिति का समर्थन करने और जल्द ही असम में राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाने की भी घोषणा की।

2. बिहार - फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनाब रमजान अली अंसारी

जनाब अंसारी ने कहा कि वर्तमान में संगठन का काम बिहार में "टुकड़े टुकड़े गैंग" जैसा है जिसे जनता के हित में सही नहीं कहा जा सकता है. संगठन में सबको एक होकर एक लक्ष्य बनाकर बसु जी के कुशल नेतृत्व में संघ के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एफपीएस डीलरों को आवंटन में कमी, कमीशन का भुगतान न होने के साथ-साथ ई-पीओएस सर्वर की समस्या जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके समाधान के लिए हमें अब आंदोलन/हड़ताल आदि के विकल्पों पर निर्णय लेना चाहिए. राष्ट्रीय स्तर । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि या तो हम सरकार का पूरी तरह से विरोध करें या समर्थन करें, तभी हमारी अहमियत सामने आएगी, बिहार राज्य राष्ट्रीय समिति द्वारा पारित सभी प्रस्तावों का समर्थन करता है और हमेशा मजबूती से राष्ट्रीय महासंघ के साथ खड़ा है।

Contd..... 2

3. बीटीडीए - असम, श्री देबेन चंद्र बोरो, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री बोरो ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा फेडरेशन के सभी कार्यक्रमों में भाग लेता रहा है, हमें राष्ट्रीय समिति द्वारा भी मान्यता प्राप्त है और हमारा संगठन प्रतिबद्ध है असम इकाई के साथ मिलकर काम करने के लिए। कार्यकारिणी की बैठक की सूचना हमारे राष्ट्रीय महासचिव को दे दी गई है। आधार सीडिंग का काम पूरा होने के बावजूद कई लाभार्थियों के नाम गायब हैं, जिससे परेशानी हो रही है, एनआरसी नहीं होने से भी परेशानी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि असम में हम संगठन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि उनकी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक कोर्ट केस दायर किया गया है, 50 से कम राशन कार्ड रखने वाले उचित मूल्य दुकान के डीलरों के लाइसेंस वापस लेने के फैसले के खिलाफ

4. दिल्ली - श्री शिव कुमार गर्ग, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री गर्ग ने कहा कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आंदोलन किए, विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हमारे राज्यों और अन्य राज्यों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। मेरी राय में, जब तक वितरण बंद नहीं होगा, तब तक सरकार समझ नहीं पाएगी। दिल्ली में जब हमने पूरी तरह से बंद कर दिया, तो सरकार ने हमारा कमीशन बढ़ा दिया, उसी तरह, अगर राज्यों के एफपीएस डीलर भी एकजुटता दिखाते हैं, अगर वे सफलतापूर्वक वितरण बंद कर देते हैं, तो सरकार कमीशन बढ़ाने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ई-पीओएस सर्वर की समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम निर्धारित करने की मांग करते हुए राज्यों द्वारा होने वाले हैंडलिंग लॉस की भरपाई से परहेज किया। उन्होंने कहा कि हम हितग्राहियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। उन्होंने राष्ट्रीय कमेटी को पूरा सहयोग देने की बात कही।

यह भी कहा गया कि दिसंबर के बाद जब खाद्यान्न की मात्रा कम हो जाएगी और व्यापारियों की आय में कमी आएगी, तो हमारे सामने एक बड़ा आर्थिक संकट होगा, ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए अगला कदम उठाना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार करने के बाद। उन्होंने केंद्रीय खाद्य मंत्रालय से एक महीने में दोहरा लेन-देन बंद करने का अनुरोध करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि दिल्ली में एक माह का बैकलॉग चल रहा है।

5. हरियाणा - श्री शिशपाल गोदारा, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री शिशपाल गोदारा ने आज की बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा। उन्होंने देश भर में बायोमेट्रिक्स से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समाधान का आग्रह किया और कहा कि हरियाणा में दो पोर्टल चलने के कारण भी समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने 2G को 5G नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए राष्ट्रीय समिति से मांगों को उठाने की पुरजोर वकालत की और मांग की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय कमेटी जितनी मेहनत कर रही है और बिना संसाधनों के देश के सभी डीलरों के लिए काम करती है, कुछ लोगों की वजह से हमारा सिर झुक जाता है, ऐसे लोगों के लिए हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि "वन नेशन वन राशन कार्ड" के कारण कुछ राज्य सरकारों द्वारा मांग के अनुसार खाद्यान्न आवंटित करना आवश्यक है। विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा राज्य इससे प्रभावित हैं, इसलिए राष्ट्रीय समिति द्वारा उन स्थानों में अतिरिक्त आवंटन के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जहां प्रवासी मजदूरों का आगमन अधिक है।

Contd..... 3

उन्होंने आगे कहा कि कमीशन कितना भी बढ़ जाए, हमारी एक स्थायी आय होनी चाहिए, जिसे वर्तमान में गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित अनुपात में होने पर भी राहत दी जा सकती है। (रु. 20,000/- प्रति माह प्रति एफ. पी. एस.), उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय संघ लगातार अपने कार्य में लगा हुआ है, इसलिए हरियाणा राज्य हमेशा संघ के साथ है।

6. झारखंड - श्री ओंकार नाथ झा, फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

श्री ओंकार नाथ झा ने राज्य सरकार की लचर नीतियों पर प्रहार किया. हैंडलिंग लॉस का एक किलो प्रति क्विंटल देने पर गोदामों से प्राप्त खाद्यान्नों पर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वर सिस्टम को गंभीरता से लेने के साथ ही e – PoS उपकरणों का उन्नयन भी किया जाना चाहिए। मासिक आवंटन में की जा रही कटौती पर आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से इसकी जांच की मांग की है जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे। उन्होंने NFSA से राज्य सरकार को अपने ग्रीन कार्ड में स्टॉक डायवर्शन के बारे में विस्तार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

उन्होंने कहा कि उन्हें अपने राज्य के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी शिकायतें मिल रही हैं कि एफसीआई से पीएमजीकेएवाई खाद्यान्न उठाव और राज्य के गोदामों में वितरण के बीच कुछ घोटाले हो रहे हैं। अगली कार्रवाई के लिए इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के डीलर्स के लिए निश्चित आमदनी के लिए अगला प्रयास करना जरूरी है। आय जो गुजरात की तर्ज पर है और राष्ट्रीय समिति की मांगों के अनुसार है, और आज फिर से एक बड़े निर्णायक आंदोलन की रूपरेखा पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, उन्होने कहा कि झारखंड के सभी डीलरों को पूर्ण विश्वास है राष्ट्रीय कमेटी पर और हम सब मिलकर आंदोलन को मजबूत करेंगे।

उन्होंने सभी राज्यों के फेडरेशन के पदाधिकारियों से अपील की कि वे मात्र एक रुपया वसूल कर आर्थिक सहयोग करें। 1/- प्रति डीलर प्रति माह मूवमेंट फंड बनाकर उसे पश्चिम बंगाल इकाई के बैंक खाते में फिलहाल जमा करने की अपील की।

7. जम्मू-कश्मीर - श्री अब्दुल रहीम शाह, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

उन्होंने देश भर में कमीशन बढ़ाने, मानदेय की नीति निर्धारित करने और राज्य सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया। और सरकार। भारत के हैंडलिंग लॉस अलाउंस को लागू करने के लिए जो एक वास्तविकता है।

उन्होंने कमीशन नहीं मिलने, e-PoS मशीन के अपग्रेडेशन पर, पेपर रोल की कीमत नहीं मिलने के साथ-साथ अनलोडिंग चार्ज नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने यह भी कहा कि हमें गुजरात की तर्ज पर मानदेय तय करने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि राशि रु. 20,000/- बहुत कम है.. कमीशन का आधा भुगतान करने का प्रयास किया जाए, इसके लिए भी हमने भारत सरकार के सचिव को सारी जानकारी दे दी है जो कानूनी प्रक्रिया में है, सीएससी खोलने का कार्य जम्मू-कश्मीर में चल रहा है, कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है।

8. केरल - फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव श्री अरविन्द बाबू

श्री अरविन्द बाबू ने अपना सम्बोधन मलयालम भाषा में दिया जो बहुतों के लिए पराया है। उन्हें निर्देश दिया गया कि मलयालम शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद करें और उन्हें राष्ट्रीय समिति में पोस्ट करें।

Contd..... 4

9. महाराष्ट्र - श्री डी. एन. पाटिल, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री डी. एन. पाटिल ने ई-पीओएस और सर्वर की समस्या को राष्ट्रीय समस्या बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य और वितरण प्रतिशत में बहुत परेशानी है, कम हो चुका है । उन्होंने यह भी कहा कि 4जी आने के बाद भी इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। इससे निजात पाने के लिए सोचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन्हें अधिक कमीशन मिलता है वे चुप रहते हैं और जिन्हें कम मिलता है वे हंगामा करते हैं, उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यापारियों को अधिक परेशानी होती है।

उन्होंने अनुरोध किया कि एक निश्चित आय के लिए पूरे भारत से एक सुझाव आना चाहिए, उन्होंने अवगत कराया कि सीएससी के तहत महाराष्ट्र में बिजली बिलों की वसूली उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से, गृह कर (Home tax) शुरू किया गया है। राज्य सरकार की ओर से आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र में सही काम करने वाले डीलर को सही अनाज मिलता है, गलत करने वाले परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य हमेशा संघ के साथ रहा है और हम भविष्य में भी हमेशा साथ रहेंगे।

10. नागालैंड - श्री मीजियांग गोनेमेल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री मीजियांग गोनेमेल फेडरेशन के कहा कि सभी राज्यों में सर्वर, ई-पीओएस की समस्या है, पीडीएस डीलरों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सभी उपायों पर विचार करना आवश्यक है, सर्वर पर सभी सरकारें कहती हैं कि यह एन.आई.सी. की समस्या है। फिर इसे ठीक क्यों नहीं किया जाता? मुख्य मुद्दा यह है कि हम "धरना" कितना प्रदर्शित करते हैं लेकिन सरकार, हमें हमारा हक नहीं दे रही है, पहली बार हमें रु. 20/- मैदानी क्षेत्र के लिए और पहाड़ी क्षेत्र के लिए रु. 37/- प्रति क्विंटल वृद्धि, सीएससी, एलपीजी की घोषणा की, लेकिन इससे हमारी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं होगी, हमें नई नीति बनाकर आंदोलन करना होगा, आवंटन देर से प्राप्त होता है, लाभार्थियों के साथ समस्या है। पहाड़ी क्षेत्र में भी चीनी, खाद्य तेल, दाल आदि उपलब्ध नहीं है, हमारा 2019 – 20 में 17 करोड़, 2020 – 21 का 19 करोड़ का कमीशन बाकी है। राष्ट्रीय समिति को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारी वित्तीय कठिनाइयों का समाधान करना चाहिए। हम पहाड़ी क्षेत्र के सभी राज्य संघों के काम की सराहना करते हैं और हम सभी एक साथ आंदोलन में रहेंगे। उन्होंने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से टाइड ओवर आवंटन के वितरण को रोकने की मांग की, जिसे एफपीएस के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

11. ओडिशा - श्री नागेंद्र जेना, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार, हमारे राज्य में पीडीएस पर काम कर रही है। मार्च 2022 के बाद किसी भी निजी राशन डीलर के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने का आदेश जारी किया है, उन्होंने सभी राज्यों के दोस्तों से अपील करते हुए कहा कि सभी हमारी रक्षा करें। हमें कमीशन नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा, ऐसे में हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की स्थिति में आ गए हैं, हमारे डीलरों की हालत दयनीय है, फेडरेशन से हमारी मदद करने का अनुरोध करें।

12. राजस्थान - श्री सेवाराम जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव

श्री सेवाराम जी ने कहा कि हमारे राज्य में भी नेटवर्क और ई-पीओएस की समस्या बनी हुई है। हमारा कोई भी

Contd..... 5

कमीशन बकाया नही है। राज्य सरकार के बजट से पहले हम जोर-शोर से अपनी मांगों को रखने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य समिति की ओर से राजस्थान राज्य हमेशा से संघ का कार्य करता रहा है और आज जो भी प्रस्ताव पारित हुए राजस्थान उसके साथ है। उन्होंने सुझाव दिया कि फेयर प्राइस शॉप डीलर्स को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जानी। चाहिए।

13. तेलंगाना - श्री नाइकोटी राजू, फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

श्री नाइकोटी राजू 4G तेलंगाना में चालू है, हम 200 – 400 लाभार्थियों को आराम से राशन देते हैं, हर महीने हमें कमीशन मिलता है। दिसंबर-जनवरी के भीतर हमारी सरकार, हमें बहुत कुछ देने जा रही है, सरकार द्वारा हमें पांच लाख का बीमा देने का प्रस्ताव दिया है, हमने दस लाख की मांग की है। हमारी सरकार, अब हमारे पक्ष में है और कहा कि तेलंगाना के डीलरों को अन्य सभी राज्यों की तुलना में अधिक सुविधाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम फेडरेशन के फैसले के साथ हैं। उन्होंने हैदराबाद में एक राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाने का भी अनुरोध किया।

14. उत्तर प्रदेश - फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश तिवारी

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 100 प्रतिशत आधार सीडिंग हो चुकी है। ई-पीओएस में दिक्कत है लेकिन बिक्री बाधित नहीं है। राज्य में कमीशन की राशि लंबित है, हमें ई-पास नहीं मिल रहा है, हम देश के सभी राज्यों में सर्वर की समस्या और कमीशन और एक निश्चित आय के संबंध में फेडरेशन के निर्णय के साथ हैं। हम चाहते हैं कि सभी डीलरों की समान निश्चित आय हो, अगर गुजरात की तर्ज पर कोई नीति बनाई जाती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, यह राशि 50,000/- रुपये प्रति माह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि राज्य सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। हमें जो कुछ भी मिलता है, वह केंद्र सरकार ही दे सकती है और यह भी एक केंद्रीय योजना है, हमें आपूर्ति किए गए खाद्यान्न में बोरियों का तौल नहीं मिलता है, हमें हैंडलिंग लॉस प्राप्त करने की आवश्यकता है। राज्य हमेशा श्री बसु जी के और फेडरेशन के साथ था, है और रहेगा, आज जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, हम उनका पालन करेंगे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में करीब 40 प्रतिशत एफपीएस परिवार पंचायत में प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. पंजाब - श्री करमजीत सिंह, राष्ट्रीय सहायक - सचिव

फेडरेशन के डोरस्टेप डिलीवरी लागू की थी जिसे वापस ले लिया गया है। पंजाब चाहता है कि "एक राशन-एक कमीशन" की नीति पूरे देश में लागू हो, अब हमें पंजाब सरकार के साथ बैठक करनी थी। जो चुनाव के कारण मुख्यमंत्री के व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं हो पाया है, दस महीने से हमें हमारा कमीशन नहीं मिला है। हमारी राष्ट्रीय समिति से अनुरोध है कि पंजाब में हमारी नई कमेटी को मान्यता देकर मान्यता प्रदान करें ताकि हम पंजाब में संगठन को मजबूत कर सकें, पंजाब हमेशा नेशनल फेडरेशन के साथ रहेगा।

16. उत्तराखंड - श्री रेवाधर बृजवासी, कार्यकारी - अध्यक्ष उत्तराखंड राज्य

उन्होंने उत्तराखंड की दयनीय स्थिति पर गंभीरता से प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तराखंड इंटरनेट और ई-पीओएस की समस्याओं के कारण समस्याओं से भरा है, ई-पीओएस के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पाने की स्थिति में खाद्यान्न की कटौती की जा रही है। वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण डोरस्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक काम नहीं

Contd..... 6

करती है, अनाज को बीच के पहाड़ों पर फेंक देती है, जिससे आज के युग में भी हमें घोड़ों और खच्चरों द्वारा खाद्यान्न उठाना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप परिवहन के लिए अधिक भुगतान करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समिति इस राज्य के बारे में विशेष रूप से सोचें, हम अपनी आजीविका के लिए राशन की दुकानों में अन्य सामान भी बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी राष्ट्रीय समिति को सोचना चाहिए और हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। बाजार दर से कम पर उपभोक्ता वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पहल की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रीय फेडरेशन के साथ काम करना चाहता है और हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने मांग की कि उनके राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष श्रेणी के रूप में माना जाना चाहिए।

17. पश्चिम बंगाल - जनाब नसीम हुसैन हलदर, फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक रोल मॉडल की तरह है, जिसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय महासचिव को जाता है। हमारे राज्य में सभी के खाते में वितरण के बाद कमीशन को अपडेट किया जाता है, अब हमें प्रति क्विंटल 200 ग्राम हैंडलिंग लॉस मिलता है, जिसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स की समस्या एक आम समस्या है, जिसे हम अपने संगठन के कार्यालय के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करते हैं। आइए इसे प्राप्त करें। तय है, आधार से लिंक होने के बाद समस्या बढ़ गई है, जिसे दूर करने के लिए मैं राष्ट्रीय समिति से अनुरोध करता हूं। यहां मेडिकल और अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस ट्रांसफर किया जाता है। इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, हमारे राज्य में एडवांस लिफ्टिंग प्रचलित है। हमारे राज्य में खराब खाद्यान्न को बदलने का प्रावधान है, खाद्यान्न की सर्वोत्तम गुणवत्ता की आपूर्ति की जाती है, कोई समझौता नहीं है, त्योहार पैकेज वर्ष में दो बार त्योहारों पर दिया जाता है, जिसमें आटा, चीनी, बंगाल ग्राम (चना), सरसों का तेल, पाम तेल की आपूर्ति की जाती है, संगठन की ताकत बनाए रखने के लिए, प्रत्येक जिला और राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं, बंगाल के सभी डीलरों को डेथ क्लेम अप्रूवल (दो लाख रुपये) किया गया है।

18. पश्चिम बंगाल - श्री विश्वम्भर बसु, राष्ट्रीय महासचिव

राष्ट्रीय महासचिव श्री बिश्वम्भर बासु राष्ट्रीय समिति की बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने अपने संबोधन के पहले क्रम में सबसे बड़ी समस्या सर्वर की कमी को देश के अस्सी करोड़ लोगों और पांच लाख सैंतीस हजार डीलरों के साथ एक भद्दा मजाक बताया और कहा कि पूरा देश इससे लड़ रहा है/संघर्ष कर रहा है। डीलरों की शिकायत है कि जब किसी दुकान में ऐसी समस्या आती है तो उन्हें लाभार्थी से लड़ना पड़ता है, हम ऐसी स्थितियों पर अडिग नहीं रह सकते। भारत सरकार को निर्णय लेना होगा कि जिस दिन सर्वर डाउन हो, उस दिन केवल आधार नंबर डालकर वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। ई-पीओएस के माध्यम से अंगूठे के गलत मिलान के मामले में, आधार संख्या डालकर राशन देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पिछली यूपीए सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के गठन के दौरान, मैंने आठ बैठकों में भाग लिया था और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक राष्ट्र, एक राशन और डबल कमीशन का प्रस्ताव किया था, पहाड़ी क्षेत्र के लिए भी अलग से प्रस्ताव दिया था, हमारी कुछ मांगें मान ली गईं, हां, हम सामान्य श्रेणी में उनकी मांगों को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि हमें दुख है कि उस क्षेत्र के डीलरों को भौगोलिक खाता और छाया क्षेत्र, यदि कोई हो, देने का निर्देश दिया जाता है।

यदि किसी राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क की सूची काम नहीं कर रही है, जहां नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो हमें मैनुअल राशन देने का आदेश दिया जाए, यह प्रणाली पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में लागू है। उन्होंने आवंटन में कमी के

Contd..... 7

मुद्दे को गलत बताते हुए कहा कि राशन कार्ड के बदले राशन दिया जाता है, जिन्हें कम मिल रहा है, वे पूरे प्रमाण के साथ तथ्यों को राष्ट्रीय समिति के सामने लाएं, इसका समाधान किया जाएगा।अगर सरकार झारखंड के मामले की तरह ही राशन देने में घोटाला कर रहा है। जहां ग्रीन कार्ड में राशन डायवर्जन की आशंका है, वहां पूरे सबूतों के साथ राष्ट्रीय समिति के सामने लाकर हम इसे सीएजी के पास ले जाएंगे. हमें यह जानने की जरूरत है कि पीएमजीकेएवाई या एनएफएसए में कमी क्यों हुई और ग्रीन कार्ड योजना के तहत सरकार ने अपने संसाधनों से कितना खाद्यान्न खरीदा है। यह एक गंभीर मामला है जिस पर फेडरेशन द्वारा नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन देश के डीलरों द्वारा फेडरेशन के साथ सहयोग करने की तुलना में दस गुना अधिक खर्च करता है।

एक राष्ट्रीय फेडरेशन की बैठक में स्टेशनरी के खर्च के साथ-साथ सभागार का खर्च, नाश्ते और खाने के खर्चे के अलावा परिवहन खर्च के अलावा लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं। न्यूनतम मासिक आय गारंटी प्रति एफपीएस @ रु. 50,000/- प्रति माह विभिन्न राज्यों को देखने की जरूरत है। बिना फंड के फेडरेशन कैसे काम करेगा? फेडरेशन ने देश के डीलरों को न्यूनतम आय प्रदान करने के लिए कमर कस ली है, हालांकि यह हमारे पास आया है कि गुजरात सरकार। 20,000/- रुपये की न्यूनतम आय गारंटी तय करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता है कि केंद्र सरकार की नीति के चलते आने वाले समय में राशन की दुकानों में खाद्यान्न की कमी हो सकती है, हमें मोटे अनाज पर निर्भरता की स्थिति का सामना करना पड़ सकताहै। सभी राज्य समिति से अनुरोध किया गया है कि लाभ-हानि का लेखा-जोखा तैयार करें। संबंधित राज्यों के विधिवत अधिकृत लेखाकार द्वारा और उन्हें नवंबर 2022 के भीतर प्रधान कार्यालय को भेज दें।

बिहार, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य इकाइयों से अनुरोध किया गया है कि वे इस वर्ष के भीतर अपने-अपने राज्यों में राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित करें। साथी सरकारी सेवक घोषित करने की मांग कर रहे हैं, जिस पर मैं राष्ट्रीय समिति के सभी जिम्मेदार नेताओं से गंभीरता से विचार करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि, तमिलनाडु में, साठ वर्षीय को सेवानिवृत्त होने, स्थानांतरित करने, अन्य शहरों में काम करने के लिए कहा जाता है, जिस पर हमारे सहयोगी अन्य राज्यों से नहीं कर सकते, तमिलनाडु के डीलर विनाश के कगार पर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है।

उन्होंने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर भी विचार कर सकते हैं। 8 नवंबर को संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ मेरी मुलाकात हुई है, जहां हम अपनी समस्याओं को रखने की पूरी कोशिश करेंगे, हम आज पारित होने वाले प्रस्तावों को सरकार के नए केंद्रीय खाद्य सचिव, भारत श्री संजीव चोपड़ा जी, के सामने रखेंगे। हम चाहेंगे कि सभी राज्यों का एक प्रतिनिधि इसमें भाग ले। सीएससी कहां लागू किया जा रहा है, कहां मुश्किलें आ रही हैं, प्रत्येक राज्य को अपनी रिपोर्ट यथासंभव जल्द से जल्द राष्ट्रीय समिति को भेजनी चाहिए।

हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि जिस तरह से ओडिशा में डीलरों के लाइसेंस समाप्त करने की साजिश हो रही है, हम ओडिशा के हर डीलर के साथ खड़े हैं, हम कोर्ट जा रहे हैं। मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे कई डीलर जनप्रतिनिधि और मंत्री बन गए हैं, जिनसे हमें सहयोग लेना है, हो सके तो उनके साथ हमारी बैठक आयोजित की जाए। अलग-अलग राज्यों में काम कर रहे विभिन्न संगठनों के साथियों से हम कहना चाहेंगे कि संघ का लक्ष्य एक ही है, तो रास्ते अलग क्यों हैं। संगठन बनाकर हम लड़ाई लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को पीडी वस्तुओं के लिए सामग्री का चयन करने के बाद हमें सूचित करना चाहिए, हम उनका सहयोग करेंगे।

Contd..... 8

हम चाहते हैं कि देश के डीलर्स शॉपिंग मॉल्स की तर्ज पर धीरे-धीरे अपनी दुकानों में कंज्यूमर गुड्स रखने की आदत डालें, निश्चित तौर पर इससे डीलर्स को फायदा होगा। भारत सरकार ने परिचालन नुकसान (Handling Loss) से निपटने के लिए नीति तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन राज्य सरकार, इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसे फिर से भारत सरकार के सामने रखेंगे।

देश के सभी राज्यों में 75 दुकानों को मॉडल शॉप बनाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ फेडरेशन की बैठक होने जा रही है। जिन राज्यों के लिए कमीशन की राशि बकाया है - हमें विवरण के साथ भेजें, हमें डबल पोर्टल पर समस्या के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

जिस राज्य में अनाज की कमी है, वहां क्यों है, कब से है, इसकी विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय कमेटी को दी जानी चाहिए। राज्यों से डोरस्टेप डिलीवरी की समस्या आ रही है, साक्ष्य के साथ इसकी जानकारी राष्ट्रीय समिति को दी जाए, इस मामले में फेडरेशन कड़ी कार्रवाई करेगा। खाद्यान्न तौलने की जिम्मेदारी डोरस्टेप डिलीवरी की है। उन्होंने सदन से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष बैठक आयोजित करने का अनुरोध किया।

एरियर मार्जिन (बकाया कमीशन), यदि कोई हो खाते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा।

जिन राज्यों में नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वहां शैडो जोन की जानकारी दें। उन्होंने 2023 में भारत सरकार को नए साल का तोहफा देने का प्रस्ताव रखा।

तीन प्रमुख मांगों के साथ अन्य मांगों को लेकर अखिल भारतीय महासंघ 31 दिसंबर 2022 तक का अल्टीमेटम देने जा रहा है, यदि उन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो

- 2 जनवरी 2023 को सभी प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
- 16 जनवरी 2023 को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन।
- 24 जनवरी 2023 को सभी राज्यों की राजधानी में राज्य स्तरीय आंदोलन।
- 1 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक जबरदस्त कार्यक्रम।

<u>हमारी तीन मुख्य मांगें हैं</u> :-

1) ई-पीओएस डिवाइस को 4जी में अपग्रेड करना और बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य रूप से लागू करने के परिणामस्वरूप "सर्वर" के बार-बार डाउन होने के कारण डीलरों और कार्डधारकों दोनों की मदद करने की तुलना में अधिक समस्याएं हुई हैं। "नेट", उंगलियों के निशान का बेमेल होना, ओटीपी की विफलता आदि ऐसे उत्पीड़नों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसी आकस्मिकताओं के तहत संबंधित कार्डधारक को आधार संख्या डालकर ई-पीओएस के माध्यम से राशन के वितरण की अनुमति देकर इसका उपचार किया जाना चाहिए।

2) सभी राज्यों में हैंडलिंग लॉस को लागू करें।

3) 50,000 / - प्रति माह की निश्चित आय, या गुजरात सरकार के प्रस्ताव के अनुसार मानदेय तय करें।

Contd..... 9

आज का संगठनात्मक निर्णय :-

1) राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पुष्प राज देशमुख जी (काका) को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था - उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं।

2) पिछली बैठक में श्री डी.एन. पाटिल को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसकी घोषणा वे महाराष्ट्र में करना चाहते हैं। इसका फैसला सदन के सभी सदस्य करेंगे, लेकिन वे इस पर राजी नहीं हुए। सदन ने श्री पाटिल से दिसंबर 2022 के भीतर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्तर की बैठक बुलाने का अनुरोध किया।

3) सदन ने कार्यकारी अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ झा को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सौंपा, हालांकि श्री पाटिल ने कहा कि वे जनवरी 2023 से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार करेंगे।

4) राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि अगले निर्णय तक श्री ओंकार नाथ झा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे, उन्होंने दिसंबर 2022 तक की तिथि निर्धारित की है।

5) अंत में जम्मू-कश्मीर के दोनों नेताओं को विवाद खत्म करने की सलाह दी गई, दूसरे राज्यों में भी विवादों से बचने की बात कही गई।

6) पंजाब राज्य को राज्य समितियों की सूची मान्यता के लिए राष्ट्रीय समिति को भेजने का निर्देश दिया गया।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में शामिल होना :-

आज (1) **बिहार, पटना से श्री बरुन कुमार सिंह**, (2) **खगड़िया, झारखंड से श्री राजेश कुमार सिंह** (3) **दुमका, झारखंड से श्री राजेंद्र प्रसाद साह**, (4) **जनाब अब्दुस पाकुड़, झारखंड से सलाम**, (5) **जमशेदपुर, झारखंड से श्री प्रमोद कुमार गुप्ता** अखिल भारतीय फेडरेशन की **राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया**।

उत्तराखंड के श्री रेवाधर बृजवासी को राष्ट्रीय महासंघ में **सहायक सचिव** के पद पर पदोन्नत किया गया है।

फेडरेशन के उपाध्यक्ष श्री जॉनी नेल्लोर के अनुरोध पर **श्री जॉनसन विलाविनाल** को भी राष्ट्रीय समिति में **सहायक सचिव** के रूप में शामिल किया गया है।

फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री सेवाराम जी के अनुरोध पर राजस्थान के **बूंदी से श्री मदन गुर्जर** को राष्ट्रीय महासंघ में **राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य** के रूप में शामिल किया गया है।

यह निर्णय लिया गया कि अब से सभी **बीटीआर एफपीएस डीलर्स और एजेंट्स एसोसिएशन** के एक नेता डायस की शोभा बढ़ाएंगे। प्रार्थना के अनुसार **ऑल असम एफपीएस डीलर्स एसोसिएशन** को एक **संबद्धता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा**।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय एवं सूचनाएं :-

आज की राष्ट्रीय समिति ने श्री पुष्प राज काका जी को संघ के संरक्षक के रूप में भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

Contd..... 10

राष्ट्रीय महासचिव के विशेष प्रस्ताव पर पूर्व केन्द्रीय खाद्य सचिव श्री सुधांशु पाण्डेय जी को अखिल भारतीय संघ के सह सलाहकार के रूप में सदन ने ध्वनिमत से स्वीकृति प्रदान की। अध्यक्षीय भाषण के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सुबह से ही आंदोलन की तैयारी करना शुरू कर दें।

राष्ट्रीय महासचिव श्री विश्वम्भर बसु ने सदन को बताया कि आधार बायोमेट्रिक्स यूआईडीएआई द्वारा डेटा को हर 10 (दस) वर्षों में अपडेट किया जा सकता है।

सरकारआटा की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त गेहूं के स्टॉक को किश्तों में बेच सकते हैं।

राष्ट्रीय समिति शीघ्र ही आज पारित सभी प्रस्तावों को एक अल्टीमेटम के रूप में दाखिल करेगी।

आज की राष्ट्रीय समिति की बैठक का समापन राष्ट्रगान के गायन के साथ हुआ।

आज का बजट-पूर्व बैठक व्यय

विवरण	राशि
सभागार बुकिंग	20,000.00
डेकोरेटर	2,200.00
फूड(भोजन)	32,000.00
फ्लेक्स	650.00
Writing (लिखने का) पैड एवं जेरोक्स → पश्चिम बंगाल राज्य इकाई द्वारा किया गया व्यय	
कुल	**54,850.00**

ओंकार नाथ झा
बैठक के अध्यक्ष